राष्ट्रीय खबर

केंद्रीय उपभोक्ता विभाग ने दिल्ली में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 2017 मनाया

श्री राम विलास पासवान, केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कहा है कि सरकार उपभोक्ताओं को डिजिटाईजेशन के पूर्ण लाभ उपलब्ध कराने और ऑनलाइन व्यवस्था से जुड़े जोखिमों के विरूद्ध सुरक्षोपाय करने के लिए पहले से ही सही दिशा में कार्य कर रही है।

- श्री पासवान ने कहा कि यह प्रौद्योगिकी का युग है और इस डिजिटल युग में उपभोक्ताओं को शिक्षित करना और उनके विवादों का निपटान करना एक चुनौती है।
- हमारे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन अभिसरण कार्यक्रम, जहां उपभोक्ताओं के विवादों को ऑनलाइन दर्ज किया जाता है और उनका निपटान शीघ्रता से किया जाता है, के अन्तर्गत आने वाली ई-कामर्स कम्पनियों की संख्या बढ़ रही है।
- श्री पासवान ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 2017 के अवसर पर यह बातें कही। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 2017 "डिजिटल युग में उपभोक्ता अधिकार" की थीम पर मनाया गया।
- कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय केन्द्रीय उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान द्वारा की गई। श्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री, इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।
- श्री पासवान ने जानकारी दी कि पैकबंद वस्तुएं नियमों में, यह अधिदेश देने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि यदि ई-कामर्स कम्पनियां ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर बिक्री के लिए पैकबंद वस्तुओं की पेशकश कर रही हैं तो उन्हें अपनी साईटों पर अनिवार्य घोषणाएं प्रस्तुत करनी होंगी।
- उन्होंने सुझाव दिया कि डिजिटल जागरूकता कार्यक्रमों का सृजन करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दोनों को साथ मिलकर कार्य करना होगा और नॉसकॉम के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर से अनुरोध किया कि वे कम्पनियों को आचार संहिता का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे करार में उपभोक्ता के निजी डाटा को गलती से भी न छिपाएं और उस पर हस्ताक्षर करने का दबाव न डालें और उनसे अपने व्यापारिक मॉडलों के सम्बन्ध में पारदर्शिता लाने के लिए भी कहा जाए।
- केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि इंटरनेट का खुलापन, पहचान की कमी और उपयोगकर्ताओं, विशेषकर प्रथम बार उपयोगकर्ताओं, की सुरक्षा के प्रति समझ

का कम स्तर ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिनके सम्बन्ध में केन्द्रित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

रूस संघ की नौसेना के कमांडर इन चीफ एडमिरल व्लादिमीर कोरोलेव की भारत यात्रा

रूसी संघ की नौसेना के कमांडर-इन-चीफ एडमिरल व्लादिमीर कोरोलेव 15 से 18 मार्च, 2017 तक भारत की यात्रा कर रहे है।

- एडमिरल कोरोलेव की यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसेना संबंधों को मजबूत बनाना और सहयोग के नये क्षेत्रों का पता लगाना है।
- अपनी यात्रा के दौरान रूसी नौसेना के कमांडर इन चीफ ने नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा और भारतीय नौसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से द्विपक्षीय वार्ता की।
- नई दिल्ली में अपने सरकारी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एडमिरल, माननीय रक्षा मंत्री, वायुसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख और रक्षा सचिव से मुलाकात करेंगे।
- भारत रूस से सबसे अधिक रक्षा उपकरण आयात करता है और भारतीय सेना में भारी संख्या में सोवियत/रूस में बने हथियार है। भारतीय नौसेना रूस की नौसेना के साथ विभिन्न प्रकार के सहयोग करती है।
- इसमें संचालन संबंधी पारस्परिक सहयोग, प्रशिक्षण, जल माप चित्रण संबंधी सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी और नौसेना स्तर पर बातचीत के जरिये विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का आदान-प्रदान शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त भारतीय नौसेना और रूसी संघ की नौसेना 2003 से 'इन्द्र नेवी' नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कर रही है। अब तक आठ बार समुद्री अभ्यास किये गये हैं। पिछला अभ्यास दिसम्बर, 2016 में विशाखापत्तनम में हुआ था।
- एडमिरल कोरोलेव नई दिल्ली के अतिरिक्त मुम्बई जाएंगे। एडमिरल मुम्बई में पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडर इन चीफ से विचार-विमर्श करेंगे और देश में निर्मित आईएनएस मैसूर, नौसेना डॉकयार्ड और मेसर्स मजगांव डॉक एंड शिपबिल्डर्स लिमिटेड देखने जाएंगे।

एफटीआईआई और कैनन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

राष्ट्रीय खबर

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि तकनीक ने पेशेवर फोटोग्राफी एवं कला फिल्मों को परिभाषित करने में अहम भूमिका निभाई है।

- तकनीक की बारीकियों के प्रति उभरती हुई युवा प्रतिभाओं के रूझान ने युवाओं की सीखने की क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।
- यह पहल एफटीआईआई के माध्यम से प्रौद्योगिकी एवं युवा प्रतिभा का सही मिश्रण सुनिश्चित करेगी।
- उन्होंने ये बातें भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान, पुणे और कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान कहीं।
- इस अवसर पर कैनन इंडिया के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री कज़ुतदा कोबायशी भी उपस्थित थे।
- भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान और कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच यह समझौता ज्ञापन देशभर के विभिन्न कस्बे और शहरों में लघु अवधि के पाठ्यक्रमों के माध्यम से फिल्म शिक्षा को बढ़ावा देगा।
- एफटीआईआई की अनोखी पहल एसकेआईएफटी (स्किलिंग इंडिया इन फिल्म एंड टेलीविज़न) के अंतर्गत कौशल उन्मुख प्रकृति के ज़्यादातर पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों को प्रस्तावित किया गया है, जिनको राज्य सरकारें, विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न शिक्षा संस्थानों के सहयोग से चलाया जाएगा।

'दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम एशिया में रेल परिवहन कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने' पर दो दिवसीय बैठक का नई दिल्ली में शुभारंभ

राष्ट्रीय खबर

'दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम एशिया में रेल परिवहन कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने' पर दो दिवसीय बैठक आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र के एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (एस्कैप) द्वारा रेलवे के बीच सहयोग के लिए संगठन (ओएसजेडी) और भारत

सरकार के रेल मंत्रालय के सहयोग से आयोजित की गई।

- रेल परिवहन को सुदृढ़ करने और दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच कनेक्टिविटी सुलभ कराने पर चर्चाएं हुईं।
- भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु के अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान, भारत, रूसी संघ, कजाकिस्तान, तुर्की और अन्य देशों के प्रतिनिधिगण भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
- इस बैठक में दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया के भीतर सीमापार रेल परिवहन को मजबूत करने के लिए अभिनव उपायों की समीक्षा एवं पहचान करने पर विशेष जोर दिया गया, जो अपने विशाल सन्निहित भूभाग के बावजूद पूरी दुनिया के सबसे कम कनेक्टेड एवं एकीकृत उप क्षेत्रों में से एक है।
- उप क्षेत्र में आर्थिक विकास को नई गति देने, व्यापार एवं परिवहन कनेक्टिविटी को बढ़ाने और लोगों के रहन-सहन में सुधार के लिए रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है।
- बैठक में दक्षिण एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के नौ देशों के सरकारी अधिकारीगण एवं नीति निर्माता एकजुट हुए और इसके साथ ही रेलवे से जुड़े विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधिगण, कनेक्टिविटी विशेषज्ञ एवं शिक्षाविद और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए ।

भारत की नदियों में छोटी पथरीली चट्टानों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन

केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की ओर से भारत की नदियों में छोटी पथरीली चट्टानों के प्रबंधन को लेकर 17 मार्च 2017 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

- एक दिवसीय इस राष्ट्रीय सम्मेलन में एनजीआरबीए के विशेषज्ञ सदस्य डॉ. एम.ए. चिताले, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर विनोद तरे, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर ए.के.गोसेन, पुणे स्थित सीडब्ल्यूपीआरएस के निदेशक डॉ. एम. के. सिन्हा सहित कई विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- सम्मेलन का उद्घाटन केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती करेंगी।
- यह बात सर्वविदित है कि केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती ने भारतीय नदियों में छोटी पथरीली चट्टानों के प्रबंधन के विषय में

राष्ट्रीय खबर

तुरंत प्रभाव से व्यापक कार्य नीति बनाने की आवश्यकता पर पहले ही बल दिया था।

- ऐसे में मंत्रालय का मानना है कि इस तरह की किसी भी नीति को संबंधित हितधारकों के साथ गहन परामर्श एवं व्यापक चिंतन के बाद ही विकसित किया जा सकता है।
- भारत की नदियों में छोटी पथरीली चट्टानों के प्रबंधन का विषय पिछले कुछ समय से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
- नदियों में छोटी पथरीली चट्टानों के प्रबंधन को लेकर एक व्यापक नीति तैयार करने की आवश्यकता को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। दरअसल बाढ़, पर्यावरण, नदी की स्थिति एवं जल परिवहन आदि पर इसके गंभीर प्रभाव पड़ते हैं।

नमामि गंगे कार्यक्रम के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए 19 अरब रुपये लागत की परियोजनाओं को मंजूरी

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की कार्यकारी समिति ने गंगा को स्वच्छ बनाने के अभियान में तेजी लाने के लिए करीब 19 अरब रुपये लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी है।

- कार्यकारी समिति की 02 मार्च, 2017 को हुई बैठक में मंजूर की गई 20 परियोजनाओं में से 13 उत्तराखंड से सम्बद्ध है जिनमें नए मलजल उपचार संयंत्रों की स्थापना, मौजूदा सीवर उपचार संयंत्रों का उन्नयन और हरिद्वार में मलजल नेटवर्क कायम करने जैसे कार्य शामिल हैं।
- इन सभी पर करीब 415 करोड़ रुपये की लागत आएगी। हरिद्वार देश के सर्वाधिक पवित्र शहरों में से एक है, जहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं।
- अनुमोदित योजना का लक्ष्य न केवल शहर के 1.5 लाख स्थानीय निवासियों द्वारा, बल्कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए इस पवित्र स्थान की यात्रा करने वाले लोगों द्वारा उत्सर्जित मलजल का उपचार भी करना है।
- इन सभी परियोजनाओँ के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण वित्त पोषण किया जाएगा। यहाँ तक कि इन परियोजनाओं के प्रचालन और रख-रखाव का खर्च भी केंद्र सरकार वहन करेगी।
- उत्तराखंड में अनुमोदित अन्य परियोजनाओं में से चार परियोजनाएं अलकनंदा नदी का प्रदूषण दूर करने से संबंधित है, ताकि नीचे की तरफ नदी की धार का स्वच्छतर प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

व्यक्ति

शशांक मनोहर ने आईसीसी चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा

पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर ने हैरानी भरा कदम उठाते हुए बुधवार को निजी कारणों का हवाला देकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद(आईसीसी) के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया।

- मनोहर ने मई 2016 में जिम्मेदारी संभाली थी। मनोहर ने आईसीसी सीईओ डेव रिचर्डसन को ईमेल के जरिए इस्तीफा भेजा, जिसमें अचानक उनके यह कदम उठाने के कारण को स्पष्ट नहीं किया गया है।
- 59 साल के मनोहर का कार्यकाल दो साल का था।
- मनोहर ने पद छोडने का फैसला किया, क्योंकि ऐसा लगता है कि बीसीसीआई ने संवैधानिक और वित्तीय सुधारों को रोकने के लिए पर्याप्त समर्थन जुटा लिया है जिसे आईसीसी की अगली बोर्ड बैठक में पारित किया जाना था।
- किसी भी सुधारवादी कदम को पारित करवाने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ती है, लेकिन संभावना है कि बीसीसीआई बांग्लादेश, श्री लंका और जिंबाब्वे को अपनी तरफ करने में सफल रहा है।
- इसी कारण से मनोहर ने तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देने का फैसला किया।
- मनोहर ने इस्तीफा देते हुए पत्र में लिखा, 'मुझे पिछले साल निर्विरोध आईसीसी का पहला स्वतंत्र चेयरमैन चुना गया था। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश की और सभी निदेशकों के सहयोग से बोर्ड के संचालन और सदस्य बोर्ड से जुड़े मामलों का फैसला करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष रहने का प्रयास किया।'

राष्ट्रीय खबर

मणिपुर में पहली बार बीजेपी सरकार, बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद की ली शपथ

मणिपुर में पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई है. राज्यपाल नजमा हेपतुल्लाह ने बीजेपी नेता एन. बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई. एनपीपी नेता यूमनाम जयकुमार सिंह डिप्टी सीएम बने हैं.

- उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 21 सीटें हासिल हुईं, जबकि कांग्रेस ने उससे 7 सीटें अधिक यानी 28 सीटों पर जीत दर्ज की.
- लेकिन बीजेपी ने 60-सदस्यीय विधानसभा में 33 विधायकों के समर्थन का दावा किया है.

- हालांकि रविवार को कांग्रेस ने भी सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन राज्यपाल ने कहा कि वह बीजेपी के दावे से सहमत हैं.
- बीरेन सिंह को सोमवार को सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था और उन्होंने राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला से मुलाकात कर राज्य में अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया था.
- इबोबी सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री बीरेन ने मणिपुर की सेवा करने का मौका देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व का आभार जताया.
- उधर, राज्य में सरकार गठन को लेकर अदालत जाने के बारे में कांग्रेस ने कहा है कि उसने अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं.
- बीरेन सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण ऐसे दिन दिया गया, जब एनडीए में शामिल नगा पीपुल्स फ्रंट के चार सदस्यों ने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार गठन के लिए बीजेपी को अपना समर्थन देने की घोषणा की.